(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं पर स्वीकृत राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन स्वीकृत और लम्बित परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) मध्य प्रदेश में तीन रेल परियोजनाएं हैं जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई थीं और जिन्हें अभी पूरा किया जाना है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) गुना -इटावा (शिवपुरी-ग्वालियर-भिंड के रास्ते) नई लाइन:

अनुमोदन का वर्ष	1985-86
लंबाई	348 कि०मी० (320 कि०मी० मध्य प्रदेश में)
प्रत्याशित लागत	256.00 करोड़ रु०
31.3.96 तक खर्च	133.21 करोड़ रु०
1996-97 के लिए परिव्यय	22 करोड़ रु०
प्रगति	56%

चरण I: गुना से शिवपुरी तक (102 कि०मी०) का कार्य पूरा हो गया है।

चरण II: शिवपुरी से ग्वालियर तक (122 कि०मी०)

शिवपुरी-खजुरी (15 कि०मी०) और ग्वालियर-पनिहार (24 कि०मी०) पर कार्य पूरा हो गया है। पनिहार-खजूरी खंड (83 किमी०) पर कार्य चल रहा है और इसे 31.12.97 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

चरण III: ग्वालियर-भिंड खंड का आमान परिवर्तन

ग्वालियर से नोनेरा (33कि०मी०) तक का कार्य पूरा हो गया है। नोनेरा से भिंड (51 कि०मी०) का कार्य चरण II के पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

चरण IV: भिंड से इटावा तक का कार्य लगभग 5 वर्ष के समय में चरण III के पूरा हो जाने के बाद शुरू किए जाने की संभावना है। इस भाग में यमुना और चंबल नदी पर दो बड़े पुल बनाने होंगे और इस कार्य को शुरू करने से पहले गहन क्षेत्र परीक्षण करने होंगे।

(ii) गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मक्सी नई लाइन:

अनुमोदन का वर्ष	1989-90
लंबाई	316 कि०मी० (216 कि०मी० मध्य प्रदेश में)
प्रत्याशित लागत	297.14 करोड़ रु०
31.3.96 तक खर्च	9.71 करोड़ रु०
1996-97 के लिए परिव्यय	0.98 करोड़ रु०

मीटर/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलकर उपलब्ध कराए जा रहे वैकल्पिक मार्गों को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना पर कार्य रोक दिया गया था। अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है।

(iii) नागदा-भोपाल खंड के 29 स्टेशनों पर रन-थ्रू लाइन, लूप लाइनों और सम्मुख कांटों से ब्लाक खंड सीमा बोर्ड तक का रेलपथ परिपथन तथा 18 स्टेशनों पर धुरा काउंटरों द्वारा ब्लाक जांच की व्यवस्था:

स्वीकृति का वर्ष	1988-89
प्रत्याशित लागत	15.12 करोड़ रु०
31.3.96 तक खर्च	12.90 करोड़ रु०

सभी 29 स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन का कार्य पूरा हो गया है। धुरा काउंटर संबंधी कार्य चल रहा है। इस कार्य के पूरा होने की लक्ष्य तारीख दिसंबर 1997 है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

In-Service Training of Academic Staff

*600. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government believe that the assessment and enhancement of quality of higher education should start with by actively involving the teaching and research staff given their pivotal role in its activities;

(b) if so, whether Government propose to lay stress on the need for initial and in-service training of academic staff and for more rigorous mechanism in the selection and training of staff for

administrative and management functions in higher education; and

(c) if so, the steps being taken to achieve this?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): UGC has identified 45 Academic Staff Colleges (ASCs) in various universities for organising orientation/refresher courses for university and college teachers. In addition, 71 Departments have been selected to conduct refresher courses for in-service teachers in the university system. National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA) conducts training programmes for college Principals. A scheme for training of university and college administrators is under formulation.

Unmanned rail level crossings in Madhya Pradesh

3951. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of unmanned rail level crossings in Madhya Pradesh as on date;

(b) the details of accidents at these crossings during the last three years indicating the lives lost and persons injured therein; and

(c) remedial measures Government propose to take to prevent accidents at these level crossings in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Total number of unmanned level crossings in Madhya Pradesh is 1810.

(b) Statistics of train accidents are maintained Railway zone-wise and not State-wise.

(c) Safety measures such as rumble strips or Speed breakers and warning signs are already installed.

Railways also conduct publicity campaigns through the media to educate the public about the safety requirements at level crossings, particularly at unmanned level crossings and hazards of not following such safety procedures.

Educative campaigns conducted through mass media including Doordarshan and Radio, targetted at road users on precautions to be taken at level crossings.

Joint ambush checks are conducted in coordination with State Govts. to enforce provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and to nab errant road vehicle drivers.

Zonal Railways have also been directed to involve village Panchayats in the public awareness programme in rural and semi-urban areas.

Village level cmapaigns have been done. Short skits have been developed and played in villages to bring about awareness.

The solution lies in the road users' observing the necessary precautions. State Govt. can help by exercising strict checks while issuing driving licences, especially to drivers of trucks, buses and other heavy traffic vehicles.

दुग्ध की मांग तथा उत्पादन

3952. श्री अनंतराय देवशंकर दवे: क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दुग्ध की मांग तथा उत्पादन का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दुग्ध की गुजरात सहित राज्यवार प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है;

(ग) क्या सरकार ने दुग्ध की उपलब्धता तथा उसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु गुजरात सहित सभी राज्यों में सहकारी दुग्ध उत्पादन संघों को स्थापित करने पर विचार किया है और क्या उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?